

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2194

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

बिजली की कम खपत करने वाले विद्युत उपकरण

2194. श्री एस.आर. पार्थिवनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विद्युत की मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत की मांग को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को बढ़ावा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बिजली की कम खपत करने वाले विद्युत कुशल इलेक्ट्रिकल उपकरणों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : राज्यों द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को दी गई सूचना के अनुसार चालू वर्ष 2019-20 (मई, 2019 तक) के दौरान देश में विद्युत आपूर्ति स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य, उज्ज्वल डिस्काम एथ्योरेंस योजना (उदय) सहित अपनी स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती हैं। ये स्कीमों सभी के लिए 24x7 विद्युत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वितरण नेटवर्क/ग्रिड कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने में उनकी सहायता करती हैं और उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति को सुकर बनाएंगी।

भारत सरकार केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से विद्युत आबंटित करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भी सहायता करती है। राज्य मांग और आपूर्ति के बीच की कमी को पूरा करने के लिए पावर एक्सचेंजों सहित विभिन्न बाजार तंत्रों के माध्यम से भी विद्युत खरीद सकते हैं।

(ग) और (घ) : एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी जो पूरे देश में घरेलू उपभोक्ताओं को सभी के लिए सस्ती एलईडी (उजाला) द्वारा उन्नत ज्योति के अन्तर्गत लाइट इमिटिंग डायोड (एलईडी) बल्ब वितरित कर रही है। आज की स्थिति के अनुसार ईईएसएल ने 35.30 करोड़ एलईडी बल्बो वितरित किए हैं जिसके परिणामस्वरूप 9180 मेगावाट की अपरिहार्य व्यस्ततम मांग के साथ 45.85 बिलियन केडब्ल्यूएच प्रतिवर्ष की अनुमानित ऊर्जा बचत और प्रति वर्ष 37.13 मिलियन टन CO₂ के जीएचजी उत्सर्जन में कमी होने का अनुमान है।

उजाला के अन्तर्गत एलईडी बल्बों के वितरण के अलावा एलईडी उद्योग ने भी मार्च, 2019 तक 111.66 करोड़ एलईडी बल्बों की बिक्री की है।

(ङ) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत विकल्प और मार्केटेड हाउसहोल्ड उपस्कर/ उपकरणों की लागत बचत संभावना के बारे में सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से स्टैंडर्ड एण्ड लैबलिंग (एस एण्ड एल) कार्यक्रम शुरू किया है। इन उपकरणों को 1 स्टार से 5 स्टार तक रेटेड किया गया जिनमें 5 स्टार सबसे दक्ष है। इस पहल से मध्यम और दीर्घावधि में ऊर्जा बचत का प्रभाव प्रत्याशित है जबकि उसी समय ऐसे बाजारों में घरेलू उद्योगों की स्थिति प्रतिस्पर्धात्मक होगी जहां ऊर्जा दक्षता के लिए मानदण्ड अनिवार्य होते हैं।

लोक सभा में दिनांक 04.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2194 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2019-20 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अनंतिम)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2019 - मई, 2019*				अप्रैल, 2019 - मई, 2019*			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	पूरी नहीं की गई मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	271	271	0	0	356	356	0	0
दिल्ली	6,065	6,064	1	0.0	6,461	6,461	0	0.0
हरियाणा	8,679	8,679	0	0.0	8,874	8,874	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	1,654	1,644	10	0.6	1,480	1,480	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	3,364	2,720	644	19.1	2,885	2,426	459	15.9
पंजाब	8,475	8,475	0	0.0	8,802	8,802	0	0.0
राजस्थान	13,313	13,300	13	0.1	11,791	11,791	0	0.0
उत्तर प्रदेश	22,897	22,817	79	0.3	22,487	22,057	430	1.9
उत्तराखंड	2,449	2,449	0	0.0	2,155	2,155	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	67,166	66,419	747	1.1	60,987	60,078	909	1.5
छत्तीसगढ़	5,765	5,764	1	0.0	4,596	4,574	22	0.5
गुजरात	21,748	21,748	0	0.0	18,094	18,094	0	0.0
मध्य प्रदेश	12,735	12,735	0	0.0	10,145	10,131	14	0.1
महाराष्ट्र	29,295	29,294	0	0.0	23,621	23,613	8	0.0
दमन व दीव	443	443	0	0.0	344	344	0	0.1
दादरा नागर हवेली	1,106	1,106	0	0.0	818	818	0	0.0
गोवा	801	801	0	0.0	594	594	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	71,893	71,892	1	0.0	57,113	57,093	20	0.0
आंध्र प्रदेश	11,709	11,702	7	0.1	9,854	9,854	0	0.0
तेलंगाना	10,772	10,771	1	0.0	10,269	10,202	67	0.7
कर्नाटक	13,569	13,568	1	0.0	12,700	12,688	12	0.1
केरल	4,888	4,878	10	0.2	4,316	4,300	16	0.4
तमिलनाडु	20,031	20,030	1	0.0	15,680	15,659	21	0.1
पुडुचेरी	517	516	1	0.1	453	444	9	2.0
लक्षद्वीप	8	8	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	61,486	61,465	21	0.0	49,218	49,103	115	0.2
बिहार	5,662	5,659	3	0.1	5,481	5,481	0	0.0
डीवीसी	3,757	3,755	2	0.1	3,048	3,048	0	0.0
झारखंड	1,505	1,495	10	0.7	1,330	1,330	0	0.0
ओडिशा	5,261	5,261	0	0.0	5,142	5,140	3	0.1
पश्चिम बंगाल	9,920	9,897	23	0.2	9,335	9,335	0	0.0
सिक्किम	78	78	0	0.0	100	100	0	0.0
अंडमान-निकोबार	58	54	4	7	58	54	4	7
पूर्वी क्षेत्र	26,182	26,144	38	0.1	23,558	23,558	0	0.0
अरुणाचल प्रदेश	127	126	1	0.6	140	138	2	1.2
असम	1,573	1,434	139	8.8	1,910	1,673	237	12.4
मणिपुर	135	134	2	1.2	197	188	9	4.8
मेघालय	336	318	18	5.5	337	337	0	0.0
मिजोरम	100	99	1	0.8	116	113	3	2.8
नागालैंड	124	123	1	0.8	157	131	27	16.9
त्रिपुरा	292	288	4	1.3	297	295	1	0.5
पूर्वोत्तर क्षेत्र	2,686	2,521	165	6.2	2,848	2,780	68	2.4
अखिल भारत	229,413	228,441	972	0.4	183,513	182,533	981	0.5

* अनंतिम

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का भाग नहीं है। बांग्लादेश को आपूर्ति छोड़कर।

टिप्पणी: राज्य यूटिलिटीयों/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट संकलित की गई है।
